



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 उप-खंड (ii)
PART II—Section 3 Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 742]
No. 742]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 24, 1996/पौष 3, 1918
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 24, 1996/PAUSA 3, 1918

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1996

का. आ. 893 (अ).—केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजन के लिए कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैंड (एन. एस. सी. एन.) को जिसके अन्तर्गत उसके सभी दल, खण्ड और अग्र संगठन भी हैं, जिन्हें भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 823 (अ), तारीख 27 नवम्बर, 1996 द्वारा विधिविरुद्ध संगम घोषित किया जा चुका है, विधिविरुद्ध घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं "विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण" गठित करती है। अधिकरण, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री डी. के. जैन से मिलकर बनेगा।

[फा. सं. 7/51/96-एन. ई.-1]
जी. के. पिल्ले, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 1996

S. O. 893 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes the "Unlawful Activities (Prevention) Tribunal" for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the National Socialist Council of Nagaland (NSCN) including all its factions, wings and front organisations as unlawful associations declared as such by the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs vide No. S. O. 823 (E) dated the 27th November, 1996. The Tribunal shall consist of Mr. Justice D. K. Jain, Judge of the Delhi High Court.

[F. No. 7/51/96-NE.I]
G. K. PILLAI, Jt. Secy.

